International Journal of Social Science and Humanities
www.humanitiesjournals.com
ISSN: 2664-8628
Received: 19-09-2026, Accepted: 19-10-2026, Published: 03-11-2026
Volume 8, Issue 4, 2026, Page No. 61-66

खाद्य सुरक्षा में 'श्रीअन्न' की भूमिका: भारतीय परिप्रेक्ष्य में

डॉ. कार्तिकेय मिश्रा [1], याचना मौर्या [2]
[1] असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत
[2] शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत
DOI: https://doi.org/10.66856/ijssh.2026.8.4.8155

सारांश
भारत जैसे विशाल और विविधता पूर्ण देश में खाद्य सुरक्षा केवल पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पोषण सुरक्षा, आर्थिक पहुंच, स्थाई कृषि तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि की अनुकूलन क्षमता से भी जुड़ी हुई है। इस संदर्भ में श्रीअन्न अर्थात् मोटे अनाज जैसे– बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, कुट्टू, साँवा, कंगनी और चेना (प्रोसो) आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह फसलें कम पानी, अपेक्षाकृत कम उर्वरक और विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों में उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। इनके पोषण गुणों में उच्च आहार—रेशा, सूक्ष्म खनिज ,पोषक तत्व तथा कुछ प्रजातियों में उच्च प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा प्रमुख है। भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं और चावल के बढ़ते प्रभुत्व ने खाद्य उपलब्धता को तो मजबूत किया है, लेकिन इसके साथ फसल विविधता, प्राकृतिक संसाधनों और पोषण संबंधी चुनौतियां भी सामने आई है। श्रीअन्न इन चुनौतियों के समाधान में एक वैकल्पिक और पूरक खाद्य प्रणाली प्रदान कर सकते हैं। विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्र, छोटे और सीमांत किसानों तथा जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों में इनकी खेती ग्रामीण आजीविका को मजबूत कर सकते हैं। भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाये जाने के कारण श्रीअन्न को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है, यह शोध पत्र भारतीय खाद्य सुरक्षा में श्रीअन्न के योगदान, पोषणीय महत्व, कृषि एवं पर्यावरणीय लाभ, किसानों की आय में वृद्धि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सरकारी नीतियों एवं उनके सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करता है। अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि, श्रीअन्न को केवल पारंपरिक अनाज के रूप में नहीं बल्कि पोषण सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और जलवायु सहिष्णु खाद्य प्रणाली बनाने के रणनीतिक साधन के रूप में देखा जाना चाहिए।

मूल शब्दः श्रीअन्न, सुपर फूड, खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा, पोषणीय अनाज, मिलेट्स, सतत कृषि, जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण आजीविका, जलवायु स्मार्ट, स्टार्टअप

प्रस्तावना

खाद्य सुरक्षा किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की आधारशिला है। भारत में खाद्य असुरक्षा की समस्या बनी हुई है। क्योंकि देश की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है और कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, जल संकट, भूमि क्षरण तथा बाजार संबंधी अस्थिरताओं से प्रभावित होता है। पारंपरिक भारतीय कृषि में मोटे अनाजों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश सहित अनेक राज्यों में इनकी खेती लंबे समय से होती रही है। हालांकि कृषि नीतियों और उपभोक्ता प्राथमिकताओं में परिवर्तन के कारण कई क्षेत्रों में गेहूं और चावल का महत्व बढ़ा है और मोटे अनाजों के क्षेत्रफल और उपभोग दोनों स्तरों में कमी आई है, इसके परिणाम स्वरूप मोटे अनाज के उत्पादन का स्तर गिर गया। वैसे भारत में श्रीअन्न का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व रहा है, ये अनाज पारंपरिक भारतीय आहार का हिस्सा रहे हैं। जिनके माध्यम से वर्तमान समय में कृषि विविधीकरण और जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के साथ–साथ सतत विकास एवं समावेशी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अतः प्रस्तुत लेख का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा में श्रीअन्न की भूमिका का विश्लेषण करना, इसके माध्यम से पोषण एवं कृषि संबंधी महत्व को समझने तथा इसके विकास में विद्यमान प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना, साथ ही अध्ययन में उन संभावित उपायों पर विचार किया जाएगा। जिसके माध्यम से श्रीअन्न के उत्पादन वितरण और अनुभव को प्रोत्साहित करके, भारत में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और पोषण संबंधी समस्याओं ने श्रीअन्न को पुनः महत्वपूर्ण बना दिया है। बढ़ता तापमान, अनियमित मानसून, सूखा, बाढ़ तथा जल संसाधनों पर दबाव ऐसी परिस्थितियां हैं | जिनमें कम पानी और कठिन परिस्थितियों में उगने वाली फसलें खाद्य प्रणाली को अधिक लचीला बना सकती हैं।

खाद्य सुरक्षा की अवधारणा

खाद्य सुरक्षा मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं और सतत विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ केवल पर्याप्त मात्रा में भोजन की उपलब्धता से नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित, पौष्टिक तथा गुणवत्तापूर्ण भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुँच सुनिश्चित होना भी खाद्य सुरक्षा का अभिन्न अंग है। खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, खाद्य सुरक्षा ऐसी स्थिति है, जिसमें सभी लोगों को हर समय सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन तक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुँच प्राप्त हो। खाद्य सुरक्षा की आधुनिक अवधारणा का विकास मुख्यतः वैश्विक खाद्य संकटों, गरीबी, कुपोषण, प्राकृतिक आपदाओं तथा कृषि उत्पादन में अस्थिरता के संदर्भ में हुआ। प्रारंभिक दौर में खाद्य सुरक्षा को मुख्यतः खाद्यान्नों के उत्पादन और उपलब्धता से जोड़ा जाता था, लेकिन समय के साथ इसकी अवधारणा व्यापक हुई। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा के चार प्रमुख आयाम माने जाते हैं— उपलब्धता (Availability), पहुँच (Access), उपयोग/उपभोग (Utilization) तथा स्थिरता(Stability)।

पहला आयाम खाद्य उपलब्धता है। इसका संबंध देश या क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आयात, भंडारण और वितरण से है। कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा खाद्यान्नों का उचित भंडारण खाद्य उपलब्धता को मजबूत करता है।

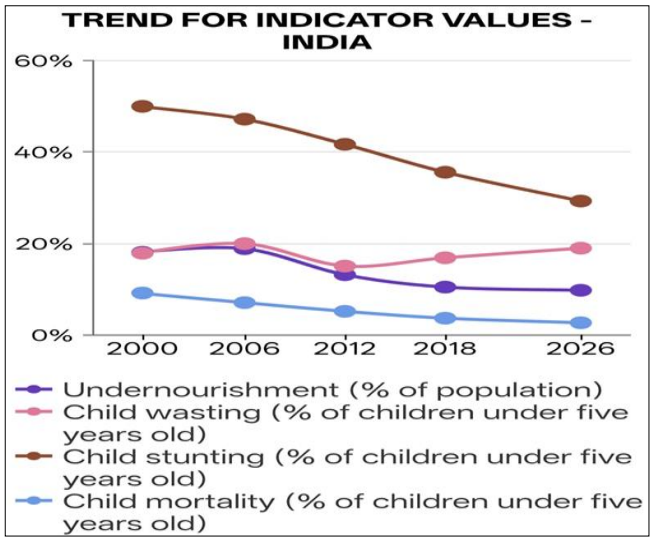
दूसरा आयाम खाद्य तक पहुँच है। केवल बाजार में भोजन उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है; लोगों के पास उसे खरीदने अथवा प्राप्त करने की आर्थिक और सामाजिक क्षमता भी होनी चाहिए। गरीबी, बेरोजगारी, आय में असमानता और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें खाद्य पहुँच को प्रभावित करती हैं।

तीसरा आयाम खाद्य का उचित उपयोग है। भोजन की गुणवत्ता, पोषण, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वच्छता तथा भोजन पकाने और सुरक्षित रखने की उचित परिस्थितियाँ इस आयाम से संबंधित हैं। पर्याप्त भोजन उपलब्ध होने के बावजूद यदि व्यक्ति उसे शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयोग नहीं कर पाता, तो वास्तविक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं मानी जा सकती।

चौथा आयाम स्थिरता है। इसका अर्थ है कि लोगों को समय–समय पर उत्पन्न होने वाले आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदा, महामारी, युद्ध, जलवायु परिवर्तन अथवा बाजार में कीमतों के उतार–चढ़ाव के बावजूद भोजन की उपलब्धता और पहुँच बनी रहे।

यदि भारत में खाद्य सुरक्षा की बात करें तो कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे द्वारा 'खाद्य सुरक्षा के बिना कोई सुरक्षा नही' विषय के साथ जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2026 के अनुसार भारत 122 देशों में 100 वे स्थान पर है, इसका स्कोर 24.1 है जो की गंभीर श्रेणी में रखा गया है। भारत में कुपोषित आबादी 9.8 प्रतिशत, बौनापन 29.3 प्रतिशत, वेस्टिंग 19 प्रतिशत तथा बाल मृत्यु दर 2.7 प्रतिशत है। यदि पड़ोसी देशों की बात करे तो नेपाल 72 वें स्थान पर जबकि बांग्लादेश 84 वें स्थान पर है जो भारत से काफी ऊपर है।

ग्राफ



श्रीअन्न की अवधारणा

भारत में मोटे अनाजों (मिलेट्स) को श्रीअन्न के रूप में ब्रांडिंग करने और इसकी अधिकारिक अवधारणा की शुरुआत वर्ष 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2023 –24 के बजट के दौरान की गई। इसके बाद 2023 में ग्लोबल मिलेट सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे वैश्विक पहचान देते हुए, इसके महत्व को रेखांकित किया गया। भारतीय श्रीअन्न (मिलेट्स) में ज्वार (सोरगम), बाजरा (पर्ल मिलेट), रागी (फिंगर मिलेट) और छोटे मिलेट्स जैसे सावाँ (बार्नयार्ड मिलेट), चेना (प्रोसो मिलेट), कोदो (कोदो मिलेट), कुट्टू (बकव्हीट), चौलाई (अमरंथस) और कंगनी (फॉक्सटेल मिलेट) शामिल हैं। श्री अन्न (मिलेट्स) आवश्यक पोषक तत्वों का उत्कृष्ट स्रोत है, इन्हें 'पौष्टिक अनाज' भी कहा जाता है। भारतीय श्रीअन्न (मिलेट्स) पोषण के मामले में गेहूं और चावल से बेहतर है। क्योंकि ये प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। ये ग्लूटेन–मुक्त भी होते हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो इन्हें सीलिएक रोग या मधुमेह वाले लोगों के लिए आदर्श बनाता है। श्रीअन्न भारत की पारंपरिक मोटे अनाजों की समृद्ध परंपरा को आधुनिक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण अवधारणा है। भारत में 2025–26 में श्रीअन्न/पौष्टिक अनाज का उत्पादन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 175.59 लाख टन होने का अनुमान है। भारत में 2025–26 में श्री अन्न/पौष्टिक अनाज (मिलेट्स) का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हैं – राजस्थान (29.86%), महाराष्ट्र (13.62%), कर्नाटक (12.91%), उत्तर प्रदेश (12.67%), गुजरात (7.25%), हरियाणा (6.92%), मध्य प्रदेश (5.87%), तमिलनाडु (4.34%), आंध्र प्रदेश (2.25%) और तेलंगाना (2.11%) और 2025–26 के दौरान, भारत से श्रीअन्न (मिलेट्स) का निर्यात 138.69 हज़ार मीट्रिक टन रहा, जिसका मूल्य 543.40 करोड़ रुपये / 61.57 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। तथा प्रमुख निर्यात गंतव्य देशों में (2025–26): संयुक्त अरब अमीरात(22.4%), सऊदी अरब (12.7%), नेपाल (7.8%), यूएसए (6.7%), और मोरक्को (3.8%)। भारत विश्व का 41 % से 47 % हिस्सा उत्पादित करता है, जो एशिया के कुल उत्पादन का लगभग 80 % है ।

खाद्य सुरक्षा और श्रीअन्न के बीच संबंध

भारत में खाद्य सुरक्षा का संबंध गरीबी उन्मूलन, कुपोषण नियंत्रण और सामाजिक न्याय से भी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मध्यान्ह भोजन तथा विभिन्न पोषण कार्यक्रमों के माध्यम से कमजोर वर्गों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही श्रीअन्न (मोटे अनाज) जैसे बाजरा, ज्वार, रागी आदि खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ अनेक परिस्थितियों यानि कम पानी और अपेक्षाकृत कम संसाधनों में अधिक उत्पादन की अवधारणा है, जिसे खाद्य उत्पादन श्रृंखला को मजबूत करने, आर्थिक पहुँच को सुनिश्चित करने, पोषण एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्पादित किए जा सकते हैं।

श्रीअन्न का महत्त्व एवं लाभ

- खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण पक्ष पोषण सुरक्षा है, आईसीएआर(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) के अनुसार श्रीअन्न में लगभग 60% से 80% कार्बोहाइड्रेट, 6% से 12% प्रोटीन तथा 1.7 % से 5.4% वसा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें आहार–रेशा, खनिज, विटामिन बी तथा अन्य जैव–सक्रिय तत्व पाए जाते हैं ।साथ ही फाइबर एवं एंटीऑक्सीडेंट, मैग्निशियम, कैल्शियम भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इनका नियमित और संतुलित सेवन विविधता पूर्ण आहार का हिस्सा बन सकता है।
- भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में खाद्य सुरक्षा के लिए विविध फसलों का उत्पादन आवश्यक है। श्रीअन्न गेहूं और चावल पर अत्यधिक निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है, अलग–अलग मौसम और कृषि परिस्थितियों के अनुकूल फसलों को बढ़ावा देने से खाद्य आपूर्ति के जोखिम को भी कम किया जा सकता है।
- वहीं दूसरी ओर श्रीअन्न को जलवायु स्मार्ट फसल माना जाता है। जो कम वर्षा वाले शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में भी आसानी से उगाये जा सकते हैं। इसलिए यह राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दक्कन के शुष्क क्षेत्रों जैसे इलाकों में कृषि के लिए उपयोगी है। इस प्रकार श्रीअन्न कृषि उत्पादन को जलवायु जोखिमों से बचाने और

दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में सहायक होते हैं।

- साथ ही किसानों के आजीविका को सही ढंग से चलाने में मदद करते हैं, कम पानी, कम तकनीकी सहयोग एवं कम रासायनिक उर्वरक में आसानी से इनका उत्पादन किया जा सकता है, साथ ही किसानों को फसल विविधीकरण का अवसर देते हैं। प्रसंस्करण, पैकेजिंग, श्रीअन्न आधारित खाद्य पदार्थ और स्थानीय बाजारों के विकास से किसानों, स्वयं सहायता समूहो तथा ग्रामीण उद्यमियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। जिससे किसानों का आर्थिक बोझ कम हो जाता है, और छोटे एवं सीमांत किसानों की आय वृद्धि का अवसर उपलब्ध कराते हैं।
- जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका– भारत के कई कृषि क्षेत्रों के जल स्टॉक में गिरावट एक समस्या बन गई है, विशेष रूप से धान जैसी अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलों की निरंतरता जल संसाधनों पर दबाव डालते हैं इसके विपरीत श्रीअन्न फसलें कम पानी में भी उत्पादन देने की क्षमता रखते हैं।
- श्रीअन्न के उपभोग से अल्प पोषण, (उचित मात्रा में भोजन न मिलना) चाइल्ड वेस्टिंग (उम्र के अनुपात में कम वजन होना), चाइल्ड स्टंटिंग (उम्र के अनुपात में कम लंबाई होना), बाल मृत्यु दर को कम करने, मधुमेह प्रबंधन, पाचन स्वास्थ्य समस्या समाधान, हड्डियों को स्वस्थ बनाने, हृदय स्वास्थ्य एवं वजन प्रबंधन, कोलेस्ट्रॉल प्रबंधन आदि में सहायक हो सकता है। क्योंकि ये पोषण तत्वों कैल्शियम, विटामिन, मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं।
- पर्यावरणीय लाभ यानि जैवविविधता का संरक्षण, कृषि जोखिम में कमी, जल संरक्षण, संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए सतत एवं समावेशी कृषि को प्रोत्साहित करने में सहायक है।
- सामाजिक आर्थिक दृष्टि से भी श्रीअन्न महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने, महिला सशक्तिकरण, छोटे एवं सीमांत किसानों, जनजाति समूह, स्थानीय अर्थव्यवस्था एवं स्थानीय खाद्य उद्योग को मजबूत करने में सहायक है।

सरकारी प्रयास

- अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के माध्यम से घोषित करवाना, जिसका उद्देश्य श्रीअन्न के पोषण उत्पादन और वैश्विक उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- भारतीय श्रीअन्न अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) हैदराबाद के माध्यम से श्रीअन्न हेतु कृषि अनुसंधान, तकनीकी विकास ,प्रशिक्षण और मूल्य संवर्धित उत्पादों के विकास तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं निर्यात को बढ़ावा देना।
- भारत में वैश्विक खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि को समावेशी बनाने हेतु, श्रीअन्न (मिलेट्स) के क्षेत्र में किये गए उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को इटली के रोम स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल 2026 से सम्मानित किया गया।
- श्रीअन्न के संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) घोषित करना, किसानों एवं उपभोक्ताओं के स्तर पर श्रीअन्न के महत्व को बढ़ावा देने के लिए उनके मूल्यों में बढ़ोतरी करना।
- श्रीअन्न फसल उत्पादन और सुरक्षा हेतु एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन तथा एकीकृत कीट प्रबंधन संबंधित तकनीकी को बढ़ावा देना। साथ ही बीज मिनीकिट के माध्यम से किसानों को उन्नत किस्म के बीज पहुंचाना।
- खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा सार्थक पीडीएस समग्र योजना (स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग – इनकम विथ ऑटोमेशन इन पीडीएस) प्रारंभ की गई , जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत करना तथा खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में सुधार लाना है, इसके तहत डिजिटल तकनीकी, स्वचालन और आधुनिक सुधारो को बढ़ावा देकर पीडीएस की पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेहिता बढ़ाई जा सकती है।
- श्रीअन्न आधारित उत्पादों में खाद्य तकनीक तथा प्रसंस्करण क्षेत्र में स्टार्टअप तथा नए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान जैसे संस्थान प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं।
- सरकार द्वारा किसानों को बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1.74 लाख क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार (NSR) स्थापित किया गया। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (NFSNM) के कृषोन्नति योजना के तहत शुरू की गई है एक पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित और आधार बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम द्वारा किया जाएगा, साथ ही राष्ट्रीय बीज भंडार में संग्रहीत बीजों का उत्पादन, प्रमाणीकरण एवं भंडार प्रबंधन साथी पोर्टल (सीड ट्रैसिबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड हॉलिस्टिक इन्वेंट्री) के माध्यम से किया जाएगा।
- वैश्विक सम्मेलन (खासकर जी 20 सम्मेलन 2023 में श्रीअन्न से बने भोजन को परोसा जाना) एवं व्यापार मेले, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्यक्रम, मिलेट फेस्टिवल के माध्यम से श्रीअन्न का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाना।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के तहत पोषण अनाजों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाता है|
- पोषण अनाज उप–मिशन के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, रागी और छोटे–मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहन दिया जाता है। सहायता में उन्नत बीज, प्रदर्शन, कृषि प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकें भी शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से राज्यों को अपनी कृषि प्राथमिकताओं के अनुसार श्रीअन्न को बढ़ावा देने की सुविधा दी गई है।
- कृषि और संरचना कोष के माध्यम से पात्र किसानो, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और उद्यमियों को कृषि और संरचना एवं प्राथमिक संस्करण सुविधा के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था उपलब्ध है।
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (पीएमएफएमई) के माध्यम से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमो को औपचारिक रूप देना, उनकी क्षमता बढ़ाना और स्थानीय खाद्य उत्पादों को बाजार से जोड़ना, इसी का परिणाम है, कि 21 जिलों में श्रीअन्न आधारित उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद के रूप में पहचाना गया है।
- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण और संरचना के विकास को प्रोत्साहित करना, पात्र परियोजनाओं के माध्यम से श्रीअन्न प्रसंस्करण इकाइयों को भी लाभ प्रदान करना।
- पीएलआई योजना के माध्यम से श्रीअन्न आधारित उत्पादों की उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना प्रारंभ कर, मोटे अनाजों से बने खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देना।

- स्थानीय खाद्य उत्पादों की पहचान और बाजार विस्तार के लिए ब्रांडिंग तथा विपणन गतिविधि को प्रोत्साहित करना, जिसके माध्यम से पारंपरिक श्रीअन्न उत्पादों को नए उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद करना।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा 'ईट राइट इंडिया' अभियान के माध्यम से संतुलित आहार और स्वस्थ खानपान के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा श्रीअन्न आधारित खाद्य पदार्थों को प्रोत्साहित करना।
- विद्यालय आधारित मध्यान्ह भोजन में स्थानीय उपलब्धता, पोषण मानकों और संबंधित दिशा निर्देशों के अनुसार मोटे अनाज शामिल करने को प्रोत्साहित करना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में श्रीअन्न की उपलब्धता को बढ़ावा देना, केंद्र सरकार राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं और उपभोक्ता पसंद के अनुसार मोटे अनाजों के खरीद एवं वितरण बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है, इसके क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार अलग–अलग नियम बना सकते हैं ।
- कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के माध्यम से श्रीअन्न और उससे बने उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना तथा इसके अंतर्गत बाजार विकास गुणवत्ता सुधार और निर्यात को सहायता जैसी गतिविधियां शामिल की गई है।

भारत में श्रीअन्न की प्रमुख चुनौतियाँ

- उत्पादन एवं उत्पादकता की समस्या–भारत में श्रीअन्न की खेती करने वाले किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों की कमी, पारंपरिक कृषि तकनीकों, सीमित सिंचाई एवं कृषि यंत्रीकरण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से कोदो, कुटकी और अन्य लघु मिलेट्स की उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है।
- किसानों को उचित मूल्य न मिलना– श्रीअन्न की खेती करने वाले किसानों को कई क्षेत्रों में अपनी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में कठिनाई होती है। गेहूँ और चावल की तुलना में इनके लिए सरकारी खरीद की व्यवस्था तथा सुनिश्चित बाजार कई स्थानों पर सीमित हैं। परिणामस्वरूप किसान अधिक लाभ देने वाली अन्य फसलों की ओर रुख कर सकते हैं।
- श्रीअन्न के दानों से बाहरी छिलका हटाना, सफाई, ग्रेडिंग, पॉलिशिंग और आटा तैयार करना कई बार श्रमसाध्य होता है। आधुनिक मशीनों और स्थानीय प्रसंस्करण केंद्रों की कमी के कारण उत्पादन लागत बढ़ती है तथा किसानों को अपनी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता।
- भंडारण एवं शेल्फ लाइफ की समस्या–प्रसंस्कृत श्रीअन्न तथा उसके आटे में नमी और वसा के ऑक्सीकरण से गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इससे स्वाद में कड़वापन और दुर्गंध विकसित होने का खतरा रहता है। इसलिए उचित पैकेजिंग, नमी नियंत्रण, भंडारण और गुणवत्ता परीक्षण की आवश्यकता है।
- उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी–आधुनिक जीवनशैली और बदलती खान–पान की आदतों के कारण अनेक परिवारों में श्रीअन्न का नियमित सेवन कम हुआ है। कुछ उपभोक्ताओं को इसके पोषण संबंधी लाभों, पकाने की विधियों तथा विभिन्न व्यंजनों में उपयोग की पर्याप्त जानकारी नहीं होती।
- श्रीअन्न से बने बिस्कुट, नूडल्स, रेडी–टू–ईट स्नैक्स और अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रभावी विपणन तंत्र आवश्यक है। कमजोर आपूर्ति श्रृंखला, सीमित वितरण नेटवर्क, ब्रांडिंग की कमी और खुदरा विक्रेताओं की अधिक लागत के कारण उत्पादों की बाजार तक पहुँच प्रभावित होती है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सीमित समावेशन–भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में गेहूँ और चावल की प्रमुख भूमिका रही है। श्रीअन्न की सरकारी खरीद, वितरण और विभिन्न पोषण कार्यक्रमों में समुचित भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि इसका लाभ विशेष रूप से कमजोर आय वर्गों तक पहुँच सके।
- अनुसंधान एवं तकनीकी विकास की आवश्यकता–श्रीअन्न की विभिन्न किस्मों के लिए अधिक उत्पादक, रोग–प्रतिरोधी तथा जलवायु–अनुकूल बीज विकसित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही कम लागत वाली प्रसंस्करण मशीनों, बेहतर भंडारण तकनीकों और नए खाद्य उत्पादों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना जरूरी है।
- किसानों में आर्थिक प्रोत्साहन की कमी–छोटे और सीमांत किसानों के लिए श्रीअन्न की खेती, कटाई, सफाई और प्रसंस्करण में लगने वाली लागत की तुलना में प्राप्त लाभ कई बार कम होता है। पर्याप्त ऋण, प्रशिक्षण, कृषि विस्तार सेवाओं और बाजार की जानकारी के अभाव में किसान इसकी खेती का क्षेत्र बढ़ाने से बचते हैं।
- क्षेत्रीय असमानताएँ एवं नीतिगत समन्वय–श्रीअन्न की खेती, प्रसंस्करण और उपभोग की स्थिति राज्यों के बीच अलग–अलग है। उत्पादन करने वाले क्षेत्रों और बड़े उपभोक्ता बाजारों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करना तथा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, कृषि संस्थानों और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के बीच समन्वय बढ़ाना आवश्यक है

सुझाव

- श्रीअन्न की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा अधिक उपज देने वाली, रोग–प्रतिरोधी तथा जलवायु–अनुकूल किस्मों का विकास किया जाना चाहिए। किसानों को वैज्ञानिक खेती, उचित बुवाई, मृदा प्रबंधन और जल संरक्षण की तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।
- किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना, श्रीअन्न की खेती को आर्थिक रूप से आकर्षक बनाने के लिए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना आवश्यक है। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से संबंधित व्यवस्थाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, सरकारी खरीद केंद्रों के विस्तार और स्थानीय मंडियों को मजबूत करने की आवश्यकता है। किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) तथा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को सामूहिक विपणन की सुविधा दी जा सकती है।
- प्रसंस्करण एवं भंडारण सुविधाओं का विकास श्रीअन्न की सफाई, छिलका हटाने, आटा बनाने और पैकेजिंग के लिए आधुनिक एवं कम लागत वाली मशीनें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने से किसानों की लागत कम हो सकती है और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक भंडारण, नमी नियंत्रण तथा उपयुक्त पैकेजिंग से उत्पाद की गुणवत्ता और टिकाऊपन बनाए रखने में सहायता मिलेगी।
- बाजार एवं मूल्यवर्धित उत्पादों का विस्तार श्रीअन्न से बिस्कुट, दलिया, नूडल्स, स्नैक्स, रेडी–टू–कुक खाद्य पदार्थ और अन्य पौष्टिक उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। इनके उत्पादन और विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs), स्वयं सहायता समूहों

तथा स्थानीय उद्यमियों को वित्तीय सहायता और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई–कॉमर्स और प्रभावी ब्रांडिंग के माध्यम से बाजार का विस्तार किया जा सकता है।

- जन–जागरूकता एवं पोषण शिक्षा श्रीअन्न के पोषण संबंधी लाभों और विभिन्न खाद्य पदार्थों में इसके उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। विद्यालयों, महाविद्यालयों, ग्राम सभाओं, स्वास्थ्य केंद्रों और मीडिया के माध्यम से पोषण शिक्षा कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। स्थानीय व्यंजनों और आधुनिक खाद्य उत्पादों के माध्यम से श्रीअन्न को दैनिक आहार में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन–श्रीअन्न की उत्पादकता, प्रसंस्करण, पोषण गुणवत्ता और बाजार क्षमता बढ़ाने के लिए अनुसंधान में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए।
- सरकारी योजना एवं पोषण कार्यक्रमों से जोड़ना–श्रीअन्न को उपयुक्त स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली, विद्यालय पोषण कार्यक्रमों तथा आंगनबाड़ी सेवाओं में शामिल करने की संभावना पर कार्य किया जाना चाहिए। इससे किसानों के लिए मांग बढ़ सकती है और बच्चों तथा कमजोर आय वर्गों तक विविध एवं पौष्टिक भोजन पहुंचाने में सहायता मिल सकती है। इसके लिए खाद्य गुणवत्ता स्थानीय पसंद और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान (ICAR-IIMR), कृषि विश्वविद्यालयों तथा निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसानों तक नई तकनीकों और वैज्ञानिक जानकारियों का प्रभावी हस्तांतरण भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- अनुसंधान एवं तकनीकी विकास की आवश्यकता–श्रीअन्न की विभिन्न किस्मों के लिए अधिक उत्पादक, रोग–प्रतिरोधी तथा जलवायु–अनुकूल बीज विकसित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही कम लागत वाली प्रसंस्करण मशीनों, बेहतर भंडारण तकनीकों और नए खाद्य उत्पादों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना जरूरी है।
- किसानों में आर्थिक प्रोत्साहन की कमी, छोटे और सीमांत किसानों के लिए श्रीअन्न की खेती, कटाई, सफाई और प्रसंस्करण में लगने वाली लागत की तुलना में प्राप्त लाभ कई बार कम होता है। पर्याप्त ऋण, प्रशिक्षण, कृषि विस्तार सेवाओं और बाजार की जानकारी के अभाव में किसान इसकी खेती का क्षेत्र बढ़ाने से बचते हैं। इसलिए लागत के अनुरूप किसानों को उचित लाभ भी मिलना चाहिए ।
- क्षेत्रीय असमानताएँ एवं नीतिगत समन्वय–श्रीअन्न की खेती, प्रसंस्करण और उपभोग की स्थिति राज्यों के बीच अलग–अलग है। उत्पादन करने वाले क्षेत्रों और बड़े उपभोक्ता बाजारों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करना तथा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, कृषि संस्थानों और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के बीच समन्वय बढ़ाना आवश्यक है।

निष्कर्ष एवं संभावनाएँ

भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, कुपोषण की समस्या को कम करने तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने में श्री अन्न (मिलेट) की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी और साँवा जैसे अनाज भारतीय कृषि एवं खाद्य संस्कृति का पारंपरिक हिस्सा रहे हैं। इनमें उपलब्ध पोषक तत्त्व, आहार रेशा तथा विभिन्न खनिज पदार्थ इन्हें संतुलित आहार का महत्त्वपूर्ण घटक बनाते हैं। श्रीअन्न की अनेक फसलें कम पानी में उग सकती हैं, और अपेक्षाकृत प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में भी उत्पादन दे सकती हैं। इस कारण जलवायु परिवर्तन, जल संकट और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव के बीच इनका महत्त्व और अधिक बढ़ गया है। हालाँकि, भारत में श्रीअन्न की व्यापक संभावनाओं के बावजूद इसके विकास में कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इनमें किसानों को उचित मूल्य न मिलना, गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता, आधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं का अभाव, सीमित विपणन व्यवस्था तथा उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी प्रमुख हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन, कृषि अनुसंधान में निवेश, आधुनिक तकनीकों का उपयोग और किसानों को बाजार से जोड़ना आवश्यक है। साथ ही, श्रीअन्न को सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों के उपयुक्त पोषण कार्यक्रमों में शामिल करने की संभावनाओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

भविष्य की दृष्टि से श्रीअन्न के विकास की अनेक संभावनाएँ हैं। प्रथम, श्रीअन्न आधारित खाद्य उत्पादों, जैसे दलिया, बिस्कुट, नूडल्स और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है। द्वितीय, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर विकसित किए जा सकते हैं। तृतीय, श्रीअन्न की खेती को प्रोत्साहित करने से कृषि विविधीकरण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और किसानों की आय में सुधार की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं। इसके अतिरिक्त, प्रभावी ब्रांडिंग, डिजिटल विपणन और निर्यात के माध्यम से भारतीय श्रीअन्न को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अधिक पहचान दिलाई जा सकती है।

अंततः, श्रीअन्न को केवल पारंपरिक अनाज के रूप में नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और टिकाऊ कृषि के महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में देखना चाहिए। इसके उत्पादन से लेकर उपभोग तक पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सरकार, वैज्ञानिक संस्थानों, किसानों, उद्योगों और उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इस प्रकार, श्रीअन्न का समुचित विकास भारत को अधिक पोषण–सुरक्षित, कृषि–आत्मनिर्भर और जलवायु–अनुकूल खाद्य प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

सन्दर्भ सूची

1. https://www.fao.org/millets-2023/about/?utm.com
2. https://apeda.gov.in/?utm.com
3. https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-04/Report-on-Promoting-Best-practices-on-Millets-26_4_23.pdf?utm.com
4. https://wcd.gov.in/?utm.com
5. https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n21/057/89/pdf/n2105789.pdf
6. https://www.millets.res.in/publications.php?utm.com
7. https://epubs.icar.org.in/index.php/IndFarm/article/view/132582?utm.com
8. https://www.icar.org.in/en/crop-science/millets?utm.com
9. https://mofpi.gov.in/?utm.com
10. https://www.researchgate.net/publication/380219227_Shree_Anna_The_Nutritional_Powerhouse_Paving_the_Path_for_Health_Security_in_India
11. https://www.itbp.mha.gov.in/images/ITBP_MILLETS%20BOOK_HINDI.pdf
12. चापके आर आर, महेश कुमार एवं सी तारा सत्यवती 2025. नवीनतम श्री अन्न उत्पादन एवं प्रसं स्करण प्रौद्योगिकियां

पुस्तिका, भाकृ अनुप–भारतीय श्री अन्न अनुसं धान सं स्थान, हैदराबाद–500 030, भारत 102 P. (आईएसबीएनरू 978–93–94673–72–4)
13. DOI: 10.9734 / jsrr / 2024 / v30i51947
14. DOI: http://dx.doi-org/10-21760/jaims.8.4.31
15. Hidangmayum, N., Gomadhi, G., Ramasamy, M., Ejilane, S., Chitra, K., Rajeswari, E., Dhanalakshmi, K., Malathi, G., & Senthilkumar, T. (2024). Shree Anna (Millets): Promoting Nutrition and Sustainability in Agricultural Millets Map of India. *European Journal of Nutrition & Food Safety*, *16*(8), 237–246. https://doi.org/10.9734/ejnfs/2024/v16i81511
16. Kumar, V., Sharma, A. K., & Dwivedi, S. V. (2024). Shree Anna: The Nutritional Powerhouse Paving the Path for Health Security in India. *International Journal of Plant & Soil Science*, *36*(6), 230–240. https://doi.org/10.9734/ijpss/2024/v36i64625
17. श्री अन्न की भारत में उपयोगिता (n.d.). DOI: https://www.doi.org/10.33545/27068919.2025.v7.i3b.1404
18. India - Global Hunger Index (GHI) - peer-reviewed annual publication designed to comprehensively measure and track hunger at the global, regional, and country levels